राजस्थान के गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

*322. डा॰ अबरार अहमद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य के प्रत्येक जिले में कितने-कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) जिले-वार ब्यौरे विवरण- I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) सरकार ने निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों से 31 मार्च 2003 तक रॉल आउट दायित्व पूरा करने के लिए कहा है।

विवरण-I

राजस्थान के प्रत्येक जिले के उन गावों की संख्या जिन्हें टेलीफोन संविधाएं नहीं दी गई हैं।

क्र॰ सं॰	जिले का नाम	सुविधा रहित गांवों की संख्या
1.	अजमेर	45
2.	अलवर	648
3.	बांसबाड़ा	701
4.	बारन	481
5.	बाड़मेर	1016

क्र॰ सं॰	जिले का नाम	सुविधा रहित गांवों की संख्या
6.	भरतपुर	590
7.	भीलवाड़ा	550
8.	बीकानेर	273
9.	बूंदी	329
10.	चित्तौड़गढ़	1592
11.	चूरू	272
12.	दौसा	575
13.	धौलापुर	471
14.	डूंगरपुर	334
15.	हनुमानगढ़	1080
16.	जयपुर	726
17.	जैसलमेर	299
18.	जालौर	144
19.	झालावाड़	897
20.	झुंझनू	12
21.	जोधपुर	226
22.	करौली	408
23.	कोटा	210
24.	नागौर	427
25.	पाली	162
26.	राजसमंद	195
27.	सवाई माधोपुर	257
28.	श्रीगंगानगर	1964
29.	सीकर	200
30.	सिरोही	104
31.	टोंक	442
32.	उदयपुर	1225
	जोड़:	16855

Telephone Facilities in Rajasthan Villages

†*322. DR. ABRAR AHMED: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether telephone facilities have since been provided in all the villages of Rajasthan;

(b) if not, the number of villages in each district of the State which have not been provided with telephone facilities;

(c) whether Government have set any time-frame for providing telephone facilties in each village of the State; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICAIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) The district-wise detals are enclosed at Statement-I (*See* below).

(c) and (d) The Government has asked the private basic service operator to fulfil the roll out obiligation by 31st March, 2003.

Statement - I

Number of villages in each district of Rajasthan which have not been provided with telephone facilities

Sl. No.	Name of District	Number of Uncovered Villages
1	Ajmer	45
2	Alwar	648
3	Banswara	701
4	Baran	481
5	Barmer	1016
6	Bharatpur	590
7	Bhilwara	5-50
8	Bikaner	273
9	Bundi	329

†Original notice of the question was received in Hindi.

Sl. No.	Name of District	Number of Uncovered Villages
10	Chittaurgarh	1592
11	Churu	272
12	Dausa	575
13	Dhaulpur	471
14	Dungarpur	334
15	Hanumangarh	1080
16	Jaipur	726
17	Jaisalmer	299
18	Jalore	144
19	Jhalawar	897
20	Jhunjhunu	12
21	Jodhpur	226
22	Karauli	408
23	Kota	210
24	Nagaur	427
25	Pali	162
26	Rajsamand	195
27	Sawai Madhopur	257
28	Sri Ganganagar	1964
29	Sikar	200
30	Sirohi	104
31	Tonk	442
32	Udaipur	1225
	TOTAL:	16855

डा अबरार अहमद: सभापति महोदय माननीय मंत्री जी ने उत्तर में 31 मार्च, 2003 तक राजस्थान में राल आउट दायित्व पूरा करने के लिए कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि 16,855 गांव अभी तक राजस्थान में इस सुविधा से रहित हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे पास इसी सत्र में मंत्री जी से पूछे गए दो प्रश्न और उनके उत्तर हैं। एक प्रश्न 19 फरवरी का लोक सभा का अतारांकित प्रश्न संख्या 368 है और उसमें आपने यह बताया है कि राजस्थान में सुविधा रहित गांवों की संख्या 15711 है। तो संख्या घटनी चाहिए लेकिन यहां तो संख्या बढ़ रही है।

श्री सभापति: पापुलेशन के कारण संख्या बढ़ रही होगी।

डा अबरार अहमद: सभापति महोदय, गांवों की संख्या बढ़ रही है। पापुलेशन की संख्या बढ़ती तो कोई बात नहीं थी।

श्री सभापति: गांवों में ही तो पापुलेशन बढ़ती है।

डा अबरार अहमद: माननीय मंत्री जी, आपने कहा है कि 31 मार्च तक यह पूरा होने जा रहा है और हम 31 मार्च के बिल्कुल जनदीक हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उसमें गांवों की संख्या जो बढ़ रही है, इसके क्या कारण हैं? दूसरा प्रश्न मेरे पास है 27 फरवरी का जो मैंने. . .

श्री सभापति: आप तो यह पूछें कि 16,000 गांवों को कब तक कनेक्शन दे देंगे?

श्री अरुण शौरी: सर, माननीय सदस्य का क्वेशचन बहुत अच्छा है। सर, इसमें कारण यह है कि 1991 का जो सैंसस् था, उसमें राजस्थन में विलेजिस काउंट किए गए थे...

श्री सभापति: आप गांवों की काउंटिंग को छोड़िए गांवों को कनेक्शन कब तक दे देंगे, यह बताइए?

श्री अरुण शौरी: एक सैकिड, सर क्योंकि यह विलेजिस का मामला है, मैं बताना चाहता हूं कि 1991 के सैंसस् में 39,458 विलेजिस गिने गए थे। 2001 का जो सैंसस् था....

श्री सभापति: गांवों की काउंटिंग नहीं, गांव जितने बाकी रह गए हैं उनके बारे में बताइए।

श्री अरुण शौरी: उस सैंसस् में विलेजिस ज्यादा हो गए हैं।

श्री सभापति: गांव ज्यादा कहां हो गए हैं? जो गांव रह गए हैं उनमें आप कब तक व्यवस्था करेंगे?

श्री अरुण शौरी: सर, उनमें बीएसएनएल तो पूरी कोशिश कर रही है। उसमें दो आपरेटर्स हैं, स्पेशली कोई कम्पनी है—श्याम टेलीहलिंक्स, उनकी तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी 1998 में, वह बिल्कुल पूरी नहीं हुई। उसके लिए उनकी जो गारंटी थी 8 करोड की, वह जब्त कर ली गई है। उनसे एक और एडिशनल बैंक गारंटी मांगी गई थी 50 करोड़ की। कई बार चिट्ठी लिखने के बावजूद उन्होंने इसकी रिप्लाई तक नहीं दी है और मैं उस गारंटी को लिए बिना, अगर वे इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो आप देखिए कि उनके 25 करोड़ पड़े हैं, उस पर मैं जरूर ऐक्शन लूंगा अब वह प्राइवेट कम्पनी कितनी जल्दी कर सकती है यह मैं नही कह सकता। बीएसएनएल ने आफर की है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमें कंपंसेशन दीजिए तथा हम पूरा करके देंगे। यह भी हमने पूरी कोशिश की है सर। यह कितनी देर तक हो पाएगा मैं नहीं कह पाऊंगा। मगर पूरी कोशिश है कि इसी साल में हम उसको बहुत अच्छी तरह एक्सटेंड करेंगे राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसमें प्राइवेट आपरेटर्स ने सबसे कम अपनी गारंटी को फुलफिल किया है।

श्री सभापति: मुश्किल यह है कि वहां पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं और टेलीफोन भी नहीं।

श्री अरुण शौरी: सर, मुझे इसकी पूरी तवज्जुह है, मैं जरूर इस पर काम करूंगा।.. (व्यवधान)

डा अबरार अहमद : सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। सेंसस् की बात वे कह रहे हैं। सवाल का जवाब 19 फरवरी को अभी दिया गया है।

श्री सभापति: गांव के चक्कर में क्योंकि पड़ रहे हो?

डा अबरार अहमद: उसके बाद 27 फरवरी को मेरा खुद का सवाल था, उसके अंदर फिर जवाब दिया। आज 13 मार्च है। इसमें न कोई सेंसस् बढ़ती है, न गांव बढ़ते हैं। लेकिन वह सेंसस् 1991 की, 1992 की—यह सारी बातें कर रहे हैं। मैं उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं । माननीय सभापति महोदय मेरे ही 27 फरवरी के जवाब में आपने 31 मार्च, 2004 तक पूरा करने के लिए कहा और आपने वहां पर एक लाख चौवालिस हजार एक सौ बहत्तर पेंडिंग कनेक्शन बताए। तो तीनों सवालों के अलग-अलग उत्तर हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन सवालों को सरकार बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही है? तीन सवालों में तीन उत्तर तीन संख्या तीन डेटा, हर चीज अलग-अलग। इसका सेंसस् से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सभापति: यह अच्छा है कि पूछने वाले तीन नहीं हैं एक ही हैं।

श्री अरुण शौरी: सर ऐसी बात ठीक नहीं है। जो प्राइवेट कम्पनी है उसने एश्यूरेंस दिया है कि वह मार्च, 2004 तक करेंगे। उनका पास्ट रिकार्ड देख कर मैं उनके बेसिस पर कह दूं कि वह हो जाएगा, तो मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता। मैं उस पर कोशिश जरूर करूंगा।

डा अबरार अहमद: माननीय मंत्री जी के डेटा तो एक रहने चाहिए, फिगर्स तो एक रहनी चाहिए।

श्री संजय निरूपम: जब उन्होंने प्रोमिस पूरा नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए।

श्री सभापति: एक्शन ले रहे हैं।

श्री अरुण शौरी: सर उनसे 53 करोड़ जब्त किया गया है और इस कम्पनी से 8 करोड़ किया गया है। मैंने आपको अभी बतलाया कि आगे हम क्या करने वाले हैं इस चीज पर।

डा अबरार अहमद: सभापति महोदय सवाल एक है जवाब तीन हैं कम से कम एक तो जवाब मिले। (व्यवधान) सभापति महोदय मैं आपसे बहुत विनम्र आग्रह करना चाहूंगा और आपका संरक्षण चाहूंगा कि सवाल एक है और उसके तीन उत्तर अलग-अलग हैं। कम से कम जवाब तो एक हो। जब सवाल एक प्रकार के हैं तो उनका जवाब भी एक होना चाहिए। यह तीनों सवाल 19 फरवरी से 13 मार्च के बीच के हैं। उसमें दो सवाल मेरे खुद के हैं। इन तीनों सवालों पर माननीय मंत्री जी के दिए हुए तीनों जवाब भी यहां मेरे पास हैं। तो किस बात पर विश्वास करें, कौन सी बात को ठीक मानें?

श्री सभापति: ठीक है। आप कम से कम यह उत्तर देख लीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों है?

श्री अरुण शौरी: जो भी डिस्क्रिपेंसी होगी मैं स्टडी करके उनको जरूर सेटिस्फाई करूंगा।

कुमारी मैबल रिबैलो: सर मंत्री चेंज होते रहते हैं इस कारण (व्यवधान)

श्री सभापति: नेक्सट क्वेश्चन।

श्री मूल चन्द मीणा: सर, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं?

श्री सभापति: हो गया, आपकी जगह मैं बोल लिया। तसल्ली रखिए आप।

Disinvestment of EIL, STC and MUL

*323 SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Will the Minister of DISINVESTMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are thinking of disinvesting the Engineers India Ltd., State Trading Corporation and the Maruti Udyog Ltd. by the end of this year;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any process has been started in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DISINVESTMENT (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Govenment has decided to disinvest 51% equity of Engineers India Limited (EIL) through strategic sale and 10% equity of EIL in favour